[श्री राजनारायण]

कार की ऐसी कोई पालिसी नहीं है। वे कहते हैं कि अंग्रेजी अपने क्षेत्रों से इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं हो सकती है। तो मेरा निवेदन यह है कि आखिर हमारी नीति क्या है। क्या वर्तमान शिक्षा मंत्री अब तक की जो सरकार की घोषित नीति थी कि हर राज्य में वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है वह शिक्षा का माध्यम होगी, उसको बदलने जा रहे हैं या उसको कायम रखने जा रहे हैं? हमारा कहना है कि राव साहब का जो बयान आया है उससे सारे देश में एक जबरदस्त क्षोभ है। लोग चाहते हैं कि सरकार कोई न कोई सम्यक और सर्वांगीण नीति चलाए भाषा के सम्बन्ध में। शिक्षा का माध्यम उस राज्य की भाषा होगी या अनिवार्यतः अंग्रेजी चलाई जायेगी? इतना ही मुझे निवेदन करना था। प्राइम मिनिस्टर साहिबा यहां बैठी हुई हैं, अगर सरकार ने भाषा की नीति में कोई परिवर्तन किया हो तो मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को यहां पर उत्तर देना चाहिए।

REFERENCE TO DEMARCATION OF THE KLTCH BOUNDARY

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): मैं सरकार का ध्यान एक दूसरे महत्व-पूर्ण सवाल की तरफ खींचना चाहता हूं। यह समाचार मिला है कि पिछली 25 अप्रैल को कच्छ सीमा पर जो सीमांकन का काम चल रहा था भारत-पाकिस्तान के बीच में वह काम पूरा हो गया। यहां पर जब डिस्कशन हुआ था पिछले साल मार्च के महीने में तो क्षेत्र के बारे में भूपेश गुप्त ने कहा था कि 350 वर्ग मील है और प्रधान मंत्री महोदया ने साफ तौर पर इसका सुधार करने की कोशिश की थी। 6 मार्च, 1968 की राज्य सभा रिपोर्ट में पृष्ठ 3529 से जो उन्होंने कहा था मैं उसको कोट करता हूं—

> "He (Shri Bhupesh Gupta) was trying to give away more territory than is actually adjudged to lie on Pakistan's side because the figure is not 360; it is 315."

प्रधान मंत्री महोदया ने 315 वर्ग मील क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से कहा। जो समाचार मिला है उसमें यह आया है कि इससे अधिक क्षेत्र दिया गया है। केवल उदाहरण के तौर पर मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जानकारी मुझे मिली है कि विष्णुकोट और रापड़ नदी के बीच 4 वर्ग मील मीठे पानी की जो झील है और जो साधारणतया इस एवार्ड के बावजूद भी हमारे ही क्षेत्र में रहनी चाहिए थी उसको बीच में बांट कर आधी झील को पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया गया। मैं यह चाहता हूं कि सरकार एक स्टेटमेंट देकर यह बताए कि डिमार्केशन के आधार पर कितनी जमीन 315 मील या 315 मील से कितनी अधिक पाकिस्तान के हिस्से में दी गई है। दूसरा पक्ष यह था कि सारा डिमार्केशन पूरा हो जाय, उसके बाद सितम्बर 1969 तक यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में देने की बात थी। मुझे सूचना मिली है कि जैसे जैसे ये बाउन्डरी पिलर्स लगते चले गए पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के शासन ने इस क्षेत्र पर कब्जा करना चालू कर दिया है। आज यह पता भी लग जाय कि 315 मील से अधिक भूमि इस डिमार्केशन में उसको दी गई है, जिसके बारे में यहां प्राइम मिनिस्टर का एक कमिटमेंट है, तो फिर उस सारे क्षेत्र पर पाकिस्तान को अधिकार की इजाजत देना, उसको सैनिक गतिविधि या पेट्रोल या बाकी चीजों को निकालने

की इजाजत देना, इस समस्या का हम कैसे समाधान करेंगे? माननीया, मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति का जल्दी से जल्दी स्पष्टीकरण करे और इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे।

STATEMENT RE ANSWER GIVEN TO STARRED QUESTION NO. 532 ON THE 12TH DECEMBER, 1968

FUELWOOD PROCURED BY DGBR 'DEEPAK PROJECT'

THE MINISTER OF DEFENCE (SARDAR SWARAN SINGH): Madam, in the statement which I had laid on the Table in reply to Starred Question No. 532 on the 12th December. 1968. I had mentioned the names of lour local suppliers from whom firewood had been purchased. The name of one of the suppliers was given as Shri Mir Mani. It is now understood that the correct name is Shri Hira Mani and not Shri Mir Mani.

I take this opportunity to correct the answer given previously.

REFERENCE TO AGITATION IN DELHI BY UNEMPLOYED PEOPLE

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): 1 took your permission for inviting the attention of the Prime Minister to the developments relating to unemployment in the country. Madam, you, in this House, are no doubt aware that for the last two days demonstrations are taking place in the capital of India to voice the grievances of the unemployed people all over the country.

THE DEPUTY CHAIRMAN; It had been mentioned three days ago.

SHRI BHUPESH GUPTA: Yesterday a large number of young people-both boys and girls—were on hungei strike. And today, I understand, that a large number of people have also come from all parts of the country to demonstrate in order to voice their demands for solving the problems of unemployment.

I think the House will agree with me that this is a problem which needs to be given the utmost attention. In this connection—the Prime Minister is also here—I would like to know as to what are her reactions to the memoranda and letters submitted to her on behalf of the All-India Youths Federation and the All-India Students' r-ederation dated May 14th?

Now, I understand, that they have put forward certain demands and they have also pointed out that if this problem is not tackled, that will affect the lives of the young people.

I would also like to state that in the city elaborate police arrangements have been made to-day, to deal with the demonstrators. Perhaps, it has been made to arrest them. I do not know what they are going to do with them? But, I warn the Government that such steps would be absolutely wrong and highly provocative. I would, therefore, ask the Prime Minister to meet them again and discuss the problems with them and tell them as to what steps the Government are going to take to tackle the problem of unemployment among the educated youths.

THE DEPUTY CHAIRMAN : That you have already stated.

SHRI BHUPESH GUPTA: Madam, many of them are educated youths— Engineers— about 75,000 engineers are unemployed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have drawn the attention of the Prime Minister.

SHRI BHUPESH GUPTA: I would like to hear the Prime Minister and I want nothing more than this. Why should there be police arrangements in the capital to get rid of these young